



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]
No. 262]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2006/अग्रहायण 1, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2006/AGRAHAYANA 1, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2006
पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में
निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि,
नई दिल्ली

सं. 30-03/2004-डी.डी. III.—जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन, मुम्बई और अन्य बनाम देवकला कन्सलटैंसी सर्विस और अन्य के मामले में 16 अप्रैल, 2004 को 2000 की सिविल अपील संख्याएं 4655 और 5218 में लिए निर्णय में, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक निधि सृजित करने का निदेश दिया है जिसका प्रबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, अब माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों के अनुपालन में, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धाराएं 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा आदेश देती है कि अनुसूची 'क' में वर्णित धन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत के पूर्त विन्यास के कोषपाल में निहित रखा जाए जो उसके द्वारा रखा जाएगा तथा पूर्वोक्त निधियों के प्रशासन के लिए अनुसूची 'ख' में दी गयी योजना में वर्णित न्यास और निबंधनों के अनुसार, कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी पूर्वोक्त धन और उसकी आय को सुरक्षित रखेंगे;

और एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन, पूर्वोक्त निधि के प्रशासन के लिए, इससे उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में वर्णित योजना बनायी गयी है तथा उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, एतद्द्वारा यह भी आदेश दिया जाता है कि यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची 'क'

इस न्यास की संग्रह निधि के संबंध में इंडियन बैंकस एसोसिएशन द्वारा किये गये एक लाख रुपए के अंशदान को "निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि" के रूप में जाना जाएगा।

अनुसूची 'ख'

निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि के प्रशासन की योजना

इस प्रकार बनाया गया न्यास, निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करेगा। यह न्यास निधियों को प्रशासित और निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग करेगा:

- (i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के विभिन्न उपबंध कार्यान्वित करना;
- (ii) नियोजन को बढ़ावा देना;
- (iii) कौशल और उद्यमीय विकास को संवर्धित करना;
- (iv) स्वरोजगार संवर्धन की योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए सब्सिडी देना;
- (v) तकनीकी अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना;
- (vi) निवारण, पता लगाने, शीघ्र उपचार और पुनर्वास के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना;
- (vii) मनोरंजन, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक कल्याण को और आगे बढ़ाना;
- (viii) गम्भीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष गृहों की स्थापना एवं प्रबंधन को बढ़ावा देना; और
- (ix) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आनुषंगिक और सहायक हों।

2. इस निधि के उद्देश्यों का विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।

3. इस निधि का प्रबंधन और प्रशासन एक प्रबंधन बोर्ड (इसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है) द्वारा किया जाएगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (क) | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | - | अध्यक्ष |
| (ख) | सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय | - | पदेन सदस्य |
| (ग) | सचिव, भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय | - | पदेन सदस्य |

बोर्ड की बैठक - नीतिगत विषयों अथवा इस निधि से संबंधित मामलों पर निर्णय करने के लिए बोर्ड की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

बोर्ड अपने गठन में किसी रिक्ति के होते हुए भी, कृत्य कर सकेगा।

बोर्ड विनियमन, प्रबंधन और कार्य करने के तथा इस न्यास के कार्य-निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उप-विधियों को निर्मित एवं उन्हें समय-समय पर संशोधित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

इस न्यास की संग्रह निधि, 2000 की सिविल अपील संख्याएं 4655 और 5218 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16.4.2004 के निदेशों के अनुसार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज कर और ब्याज, तथा प्रत्येक संबंधित बैंक और भारतीय बैंक्स एसोसिएशन द्वारा 50 लाख रुपए के अंशदान के माध्यम से भारत संघ द्वारा वसूल की गई अधिक धनराशि की कटौतियों से मिलकर बनेगी।

निधि का निक्षेप - निधियों के बोर्ड के खातों से निधियों के आहरण को बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाली विधि से विनियमित किया जाएगा।

बोर्ड इस न्यास की निधियों का प्रबंध ऐसे समय तक करेगा जब तक कि केंद्र सरकार एक न्यास निधि के सृजन के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को संशोधित नहीं करती है, जिसके तहत मौजूदा न्यास की संग्रह निधि इस प्रकार सृजित किए जाने वाले सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी।

आशीष कुमार, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2006

In the Matter of the Charitable Endowments Act, 1890

Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities,

New Delhi

No. 30-03/2004-D.D. III.—Whereas the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 4655 and 5218 of 2000 decided on 16th April, 2004 in the case of Indian Banks' Association, Bombay and Ors. vs. Devkala Consultancy Service and Ors. directed for creation of a Fund for implementation of the provisions of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 to be managed by the Comptroller and Auditor General of India.

NOW, therefore, the Central Government in compliance of the above said directions of the Hon'ble Supreme Court, in exercise of powers conferred by Sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby order that the moneys set out in Schedule 'A' shall, as from the date of publication of this notification, be vested in Treasurer of Charitable Endowments of India to be held by him and his successors in Office upon trust to hold the said moneys and the income thereof in accordance with the trust and terms set out in the Scheme set forth in Schedule 'B' for administration of the said funds;

And it is hereby notified that the Scheme set forth in Schedule 'B' annexed hereto has, under sub section (1) of section 5 of the Act, been settled for administration of the said fund and under sub section (3) of the said section 5 of the said Act, it is hereby further ordered that it shall come into force with immediate effect.

SCHEDULE 'A'

Contribution of one lakh rupees made by the Indian Banks' Association towards the corpus of the trust to be known as the "Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities."

SCHEDULE 'B'

Scheme for the administration of the Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities, New Delhi

The Trust so created shall work for welfare of Persons with Disabilities. The Funds the Trust shall be administered and applied for following objects:-

- (i) to implement various provisions of Persons with Disabilities (Equal Opportunity, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995
- (ii) to promote employment
- (iii) to promote skill and entrepreneurial development
- (iv) to provide subsidy to grant of loans under scheme for promotion of self-employment.
- (v) to provide scholarships for pursuing technical or professional courses.
- (vi) to promote awareness about prevention, detection, early intervention and rehabilitation.
- (vii) to promote physical and mental well being through recreation, sports and cultural activities

- (viii) to promote for persons with severe disabilities the establishment and management of special homes, and
- (ix) to do all other things those are incidental and conducive to the above objects.

2. The objectives of the Fund shall extend to the whole of India.

3. The management and administration of the Fund shall be by a Board of Management (hereinafter referred to as the Board) consisting of the following members namely:

- (a) Comptroller and Auditor General of India ... Chairman
- (b) Secretary to Government of India
Ministry of Finance Member ex-officio
- (c) Secretary to Government of India
Ministry of Law and Justice Member ex-officio

Meeting of the Board – The Board shall meet at least once in three months to decide policy matters or issues related to the Fund.

The Board may function notwithstanding any vacancy in its constitution.

The Board may, frame and amend from time to time, as they think fit, byelaws for the regulation, management and conduct of business and for any other purpose connected with the execution of the trust.

The corpus of the trust fund shall comprise of the recoveries of the excess amount realised by the Union of India by way of interest tax and interest by the banks and other financial institutions, and a contribution of fifty lakhs rupees each by the concerned banks and the Indian Banks' Association, in accordance with directions of the Hon'ble Supreme Court dated 16.4.2004 in C.A. 4655 and 5218 of 2000.

Deposit of Fund – All moneys of the Fund shall be credited initially to the account of the Board of the Fund to be opened in any nationalized bank or any of its subsidiaries or any other Scheduled Bank approved in this behalf by the Government of India.

Withdrawal of Funds – Withdrawals of funds from the accounts of the Board of the fund shall be regulated in a manner to be determined by the Board.

368691708-2

The Board shall manage the funds of the Trust till such time the Central Government amends the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 for creation of a trust fund, upon which the corpus of the present trust shall be taken over by the statutory authority that shall so be created.

ASHISH KUMAR, Dy. Director General